(WDPSCA) has been launched from 1994-95 in the 7 States of the N.E. Region. The present scheme envisage development of land on watershed basis involving arable land, non-arable land, and treatment of drainage lines besides improving the skills of the local farmers through extensive training and awareness campaign.

(c) The Research Institute of Indian Council of Agricultural Research for North Eastern Hill Region at Barapani (Meghalaya) have developed some alternatives to Shifting Cultivation. According to them, measures such as bench terraces, contour bunds with vegetative barriers and combination of agriculture with horticulture, along with raising fodder/fuel trees and grasses are suitable alternatives to Shifting Cultivation.

(d) No systematic survey on the extent and distribution of area affected by Shifting Cultivation has been carried out. However, it is estimated that an area of 19.91 lakh ha. is affected by Shifting Cultivation in NE Region.

(e) Yes, Sir.

(f) Government of India through the State Government is implementing the following programmes:

(i) Scheme for Watershed Development Project in Shifting Cultivation Areas (WDPSCA) with 100 per cent Central Assistance to State Plan Programme.

(ii) Centrally Sponsored Scheme of National Watershed Development Project for Rainfed Areas (NWDPRA).

(iii) Integrated Cereal Development programme in Rice Based Cropping System Areas (ICDP-Rice).

(iv) Centrally Sponsored Scheme on Special Jute Development Programme (SJDP).

(v) Central Sector Seed Minikit Programme on Rice, Coarse Cereals and Wheat.

फलों के उत्पादन में रसायनों के घातक प्रभावों के बारे में समाचार-पत्र में छपी रिपोर्ट

4012. श्री दिलीप सिंह जूदेव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 सितम्बर, 1994 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें फलों के उत्पादन में जहरीले रसायनों के प्रयोग के घातक प्रभावों के बारे में बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार फलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाए जा रहे अभियान के इस महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(ग) फलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए उपयोग में लाए जा रहे रसायनों और सामान्य स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उनके घातक प्रभावों के संबंध में कृषि वैज्ञानिकों के विचारों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) यह एक सुस्थापित तथ्य है कि कीटनाशी दवाएं स्वभावतः विषैली होती हैं और यदि उनका प्रयोग सावधानी पूर्वक न किया जाए तो मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। व्यापक प्रयोग के लिए लागू किए जाने से पूर्व कीटनाशी दवा अधिनियम 1968 के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति द्वारा कीटनाशी दवाओं का व्यापक मूल्यांकन/जांच की जाती है और उनके सुरक्षित होने के संबंध में संतुष्टि हो जाने पर ही उनके उपयोग के तरीके आदि के संबंध में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के साथ उनका पंजीकरण किया जाता है। यदि इस कीटनाशी दवाओं का अंधाधुंध उपयोग/दुरुपयोग किया जाता है तो वे मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम अवश्य

पैदा करेगी। रासायनिक कीटनाशी दवाओं की खपत को कम करने के लिए एक नई कीट प्रबन्ध नीति को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संवर्दनात्मक, यांत्रिक तथा जैविक कीट नियंत्रण विधियों को अधिमानतः अपनाना शामिल हैं।

Shortage of milk in Delhi

4013. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Delhi has been reeling under acute shortage of milk in the recent months;

(b) if so, the reasons thereof;

(c) the steps taken to overcome the milk shortage in Delhi; and

(d) the steps taken to provide more quantity of milk to Delhites at reasonable rates?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) In order to supplement the availability of fresh milk, especially during summer, milk is rreconstituted with the help of white butter, butter-oil and skimmed milk powder so that normal supply is maintained.

गुजरात में खाद्यान्नों का उत्पादन

4014. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994–95 के दौरान गुजरात में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ तथा इस संबंध में वर्ष 1995–96 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं

(ख) क्या सरकार ने गुजरात में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) वर्ष 1994–95 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के अन्तिम प्राक्कलन अभी विभिन्न राज्यों से प्राप्त होने शेष हैं। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार गुजरात में 1994–95 के दौरान खाद्यान्न का कुल उत्पादन लगभग 47.32 लाख मीटरी टन होने का अनुमान हैं। गुजरात के लिए वर्ष 1995–96 हेतु खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 58.85 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) खाद्यान्न की उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए फसलोन्मुखी उत्पादन कार्यक्रम जैसे एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम-चावल, गेहूं और मोटा अनाज तथा राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, फसल उत्पादन में सुधार करने के लिए कम खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि करने तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार संबंधी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

Shortage of DMS Ghee

4015. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether there has been an acute shortage and scarcity of DMS ghee in the country, particularly in Delhi/New Delhi;

(b) whether the National Dairy Development Board is continuing with the export of butter to West Asia and Sri Lanka;